Sir, 'Health' is in the State List. But, for grabbing the power of the States, THE Union Government is making a lot of regulations for the schemes. Disbursement of money under the schemes is used as a tool for destroying the development of the concerned States. In 2005, when NRHM was started, the Government said that the Union Government will provide accessible, affordable and quality healthcare for rural population, especially the vulnerable groups. Now, the name has been changed to NHM. But the scheme is running in the opposite direction! For extending the availability of better healthcare, the Union Government should provide money to the States.

The States have made huge investment in health sector. The Union Government is telling that they do not have enough money for health sector. The Union Government is spending a very less amount. It is only 0.27 per cent of the GDP! There is a lot of space for improvement. Strengthening the States is one of the solutions for providing better healthcare facilities; not bypassing the right of the States. That is against the spirit of the Constitution. That will destroy the entire healthcare system, not only in rural India, but also in urban areas.

Now, here, in the House, Karnataka is requesting for its share in the health sector; West Bengal is requesting for its share; Tamil Nadu is requesting, Telangana is requesting and Kerala also requesting for their share. All across India, interests of the States are trampled upon by the Union Government. So, I request the intervention of the Union Government for protecting the healthcare system of our nation. …(*Time-bell rings*.)… Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Dr. V. Sivadasan: Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Shri Haris Beeran (Kerala).

Now, Shri Ramji Lal Suman: Need to take measures to resolve farmers' problems.

Need to take measures to resolve farmers' problems

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, पूरा देश जानता है कि एक लंबे समय से किसानों का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। यों तो उनकी कई मांगें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण

मांग यह है कि फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, एमएसपी घोषित किया जाता है, उसको कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। उपसभापति महोदय, मैं देश के किसानों के श्रम को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद इस देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। किसान खुद भूखा रहा, लेकिन उसने देश की आवश्यकताओं को पूरा किया।

उपसभापति महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह है कि इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रभावी पहल की जानी चाहिए, वह प्रभावी पहल नहीं की गई। महोदय, आप जानते हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल एक लंबे समय से अभी भूख हड़ताल पर हैं। 17 मार्च से सरकार ने घोषित किया है कि वह किसानों के गेहूं की खरीद करेगी। उपसभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार भी किसान खुले बाजार में ज्यादा गया और सरकारी खरीद केंद्रों पर कम गया। स्थिति यह है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलने के कारण किसान की प्राथमिकता खुला बाजार होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने जो गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है, सरकार किसी भी कीमत पर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती है।

उपसभापति महोदय, लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो रहा है। आप सब जानते हैं कि इससे पहले जो आंदोलन हुआ, उसमें तमाम किसान शहीद हुए और किसानों पर असत्य मुकदमे लगे। वे असत्य मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए।

उपसभापति महोदय, सबसे ज्यादा तकलीफदेह यह है कि यह जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाली कमिटी है, कृषि मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होता है। न तो उसमें किसानों के नुमाइंदे होते हैं, न ही कृषि विशेषज्ञ होते हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों की समस्याओं का हल तब तक नहीं होगा, जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती। इसलिए मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार किसानों की पीड़ा को समझे और तत्काल इस देश में घोषित करे कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Ramji Lal Suman: Shri Saket Gokhale (West Bengal), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shri M. Shanmugam (Tamil Nadu), Shri Sant Balbir Singh (Punjab), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shri Niranjan Bishi (Odisha) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Shri Mayankkumar Nayak; Demand to start Mehsana-Mumbai flights under Regional Connectivity Scheme (RCS)-UDAN (Ude Desh Ka Aam Nagrik).